Gas-based Power Plants in Punjab

4517. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government propose to instal gas-based power plants in Punjab ;

(b) if so, the details thereof and time by which these will become operative : and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Privatisation of Power Distribution in Delhi

4518. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to go in for large scale privatisation of power distribution in the capital contrary to the recommendations of the high powered Balakrishnan Committee for the creation of an Electricity Board for Delhi ;

(b) if so, whether the State Government of Delhi has been ignored in this respect even for consultation ;

(c) the steps Government propose to take to privatise power sector ; and

(d) whether any power house in Delhi has been placed under National Thermal Power Corporation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) The decision to privatise electricity distribution in Delhi is based on the recommendations of a Task Force set up under the Chairmanship of Chief Secretary, Delhi. This was subsequent to the recommendations of Balakrishnan Committee. Delhi Administration is involved in this exercise ; offers from private parties for this purpose have been invited by them.

(c) Delhi Administration is evaluating the offers received from private agencies for handing over the electricity distribution to the private sector. They are also evaluating bids received from private parties for setting up the 400/450 MW Combined Cycle Gas-based Power Project at Bawana.

(d) The management of Badarpur Thermal Power Station has been entrusted to the National Thermal Power Corporation on an agency basis by the Ministry of Power with effect from 1-4-1978.

राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति

4519. **श्री राम जेठमलानी**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन बोर्डों की दशा सुधारने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार ने इन बोर्डों द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत मूल्य का आकलन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस-किस बोर्ड का विद्युत उत्पादन लागत मूल्य अधिकतम और न्यूनतम है, तथा किस-किस बोर्ड द्वारा अधिकतम और न्यूनतम दरों पर आम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है, उनकी क्रमशः दरें कितनी-कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) संभूति आधारों पर तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता की गणना करने के बाद भी, वर्ष 1992-93 के दौरान 5 राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे थे ।

(ख) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र भार अनुपात में सुधार करने, पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने, टैरिफ संरचना को तर्कसंगत बनाने, न्यूनतम कृषि टैरिफ इत्यादि को निर्धारित करने के लिए, एक कार्ययोजना को जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किया गया था । विभिन्न राज्यों द्वारा विद्युत की आपूर्ति तथा वसूली की औसत लागत को दर्शाने वाला वितरण संलग्न है (नीचे देखिए) । बिजली आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत असम में उच्चतम तथा केरल में निम्नतम है ।